महत्वपूर्ण एवं खास

.... और अब प्लेऑफ

आईपीएल के 11 वें सीज़न के प्लेऑफ की तस्वीर साफ हो गई है। सनराइज़र्स हैदराबाद पहले और चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे स्थान पर रहते हुए सीधे फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहकर नॉकआउट मुकाबला खेलेंगी। पहली दो टीमों ने तो शुरू में ही बढ़त बना कर अपनी जगह पक्की कर ली थी लेकिन तीसरे और चौथे स्थान के लिए मुकाबला जोरदार रहा। शुरू में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स इस मुकाम तक पहुंचेंगी। किंग्स इलेवन पंजाब की भागीदारी हाल तक पक्की मानी जा रही थी लेकिन आरंभिक बढ़त के बाद टीम और प्रबंधन के बीच मनमुटाव की खबरें आईं और फिर वह पिछड़ती चली गई। यह सीज़न अब तक काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स दो साल के बैन के बाद आईपीएल में लौटी। राजनीतिक विरोध के चलते उसे अपने घरेलू ग्राउंड पर खेलने का मौका नहीं मिला, फिर भी उसने पूरे सीज़न में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार की नीलामी के बाद इस टीम को 'बुज़ुर्गों की फौज' कहा जा रहा था, क्योंकि जो भी खिलाड़ी खरीदे गए, उनमें ज़्यादातर की उम्र 30 साल से अधिक थी। लेकिन 36 साल के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर साबित किया कि क्रिकेट में अनुभव का विकल्प नहीं है।

सबसे बुरा हाल मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का हुआ। स्टार खिलाड़ियों से भरी रोहित शर्मा की टीम कभी लय में नहीं दिखी और उसे पांचवें स्थान से संतोष करना पड़ा। बाद के कुछ मैचों को छोड़ दें तो सनराइज़र्स हैदराबाद ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई है। कप्तान केन विलियम्सन ने पूरी टीम को एक साथ जोड़कर रखा है। चेन्नई की ही तरह बैन का सामना करने वाली राजस्थान रॉयल्स ने भी शुरुआती असफलताओं से सबक लिया और प्रदर्शन में सुधार कर प्लेऑफ में पहुंच गई। कोलकाता नाइटराइडर्स को उसके नए कप्तान दिनेश कार्तिक ने जिस तरह संभाला वह काबिलेतारीफ है। लेकिन बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कुछेक चमकदार प्रदर्शनों के अलावा कुछ खास नहीं कर पाई। उम्मीद है, प्लेऑफ के सारे मुकाबले बेहद रोमांचक होंगे।

अजब-गजब

इस गांव में घड़ी चलती है उल्टी दिशा में

जीहां आप माने या ना माने पर भारत के छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी गांव है जहां घड़ी विपरीत दिशा में चलती है। यानि दायें से बायीं ओर।

विपरीत दिशा में चलती है घड़ी

आप में ज्यादातर लोग घड़ी पहनते हैं और हम मानते हैं कि सभी घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा से वाकिफ हैं। दुनियाभर में घड़ी की सुइयां बायीं ओर से दाईं ओर चल कर समय की जानकारी देती हैं। ऐसे में अगर हम आप से कहें कि हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा के पास आदिवासी शक्ति पीठ से जु एक स्थान पर गोंड आदिवासी परिवारों की घी उलटी यानी दायीं से बायीं ओर चलती है तो आप मानेंगे। ये कोई आज की बात नहीं है जबसे यहां पर घड़ी के इस्तेमाल का प्रचलन शुरू हुआ है तभी से वे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलने वाली घड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्रकृति और परंपरा है वजह

गोंड समुदाय के आदिवासी परिवारों का कहना है कि उनकी घड़ी ही स्वाभाविक है जो प्रकृति के नियम अनुसार चलती है। उन्होंने अपने समय को गोंडवाना टाइम का नाम दिया है। इस विपरीत दिशा में चलने वाली घड़ी के पीछे यहां के लोगों का तर्क है कि पृथ्वी भी दायीं से बायीं ओर घूमती है। सूर्य, चंद्रमा और तारे भी इसी दिशा में अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। यहां तक कि नदी तालाब में पने वाले भंवर और पे के तने से लिपटी बेल सभी की दिशा यही होती है। इसी तरह शादी के समय फेरे भी दाहिने से बायीं ओर घूमकर लिए जाते हैं।

जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की राह नही आसान

कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। 15 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई और 104 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा को सर्वसम्पति से विधायक दल का नेता चुना और राज्यपाल वाजुवाला ने 17 मई को उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। येदियुरप्पा करीब 55 घंटे ही मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता सुख भोग पाए। उन्हें 19 मई को शाम 4 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करना था,लेकिन संख्याबल न होने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा करनी पड़ी। 222 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के पास उतने ही विधायक थे,जितने 15 मई को विजयी हुए थे। भाजपा को शायद यह उम्मीद थी कि विपक्षी कांग्रेस एवं जनता दल सेक्युलर के कुछ विधायकों को तोड़कर वह अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो जाएगी और सदन में बहुमत साबित कर देगी। राज्यपाल के दिए समय अनुसार भाजपा को यह काम पूरा होते भी दिख रहा था,परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यपाल द्वारा दिये गए समय को घटाकर केवल 28 घंटे करने पर भाजपा की सांसें फूलने लगी। उसे अपने पैरों की जमीन खिसकने का अहसास तक होने लगा। फिर भी येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जैसे मंजे हुए नेता यह दावा करते रहे कि सरकार सदन में आसानी से अपना बहुमत साबित कर देगी,परन्तु कांग्रेस एवं

जेडीएस की की मजबूत किलेबंदी ने भाजपा के मंसूबों को पूरा नही होने दिया।

येदियुरप्पा एक दिन पहले तक लगातार यह दावा करते रहे कि सदन में बहुमत परीक्षण में सफल होने के बाद शाम को भाजपा पूरे प्रदेश में शानदार जश्न मनाएगी,लेकिन इसमें सफल न होते देख वे सदन में भावुक भाषण देकर सभी विधायकों को धन्यवाद देते हए सदन से राजभवन चले गए। इस दौरान उनके मन मे पश्चाताप के भाव साफ नजर आ रहे थे ,कि सरकार बनाने का दावा पेश कर वे बहुत बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने अब संकल्प लिया है कि कर्नाटक में अब जब भी चुनाव होंगे उनमे वे 150 सीटें जीतकर शान से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे।अब वह समय कब आएगा यह तो निश्चित तौर पर नही कहा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वे फिलहाल खुद को भी पार्टी में भी अकेला महसूस कर रहे होंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में न तो भाजपा अध्यक्ष आए न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही किसी भाजपाई मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की। पद त्याग के मुश्किल समय में भी कोई बड़ा नेता उनके साथ खड़ा दिखाई नही दिया। इससे यह प्रतीत होता है कि भाजपा ने अधुरेमन से सरकार बनाने का फैसला किया हो, इसलिए भाजपा अध्यक्ष ने भी कर्नाटक जाकर येदियुरप्पा के साथ खड़े होने के बजाय दिल्ली से ही निर्देश देना उचित समझा। सवाल यह उठता है कि प्रकाश जावड़ेकर और अनंत कुमार जैसे वरिष्ठ नेता किस आधार पर यह खुशफहमी पाल चुके थे कि भाजपा कांग्रेस एवं जेडीएस के किले में सेंध लगाने में सफल हो जाएगी।

कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा को उसी चाल से मात दी है,जिस चाल से भाजपा ने इसे मणिपुर ,गोवा एव मेघालय में मात दी थी। कर्नाटक में कांग्रेस एवं जेडीएस के गठबंधन को राज्यपाल ने पंद्रह दिनों में बहुमत साबित करने का समय दिया है। फिलहाल तो संख्याबल के आधार पर यह मुश्किल भी नही लग रहा है। भाजपा को तो अब इन दोनों दलों की दोस्ती में गांठ पड़ने का इंतजार करना चाहिए। जेडीएस से गठबंधन का इतिहास इस बात की आशंका को भी बलवती बना सकता है कि यह नई सरकार अबोध गति से पांच साल चल सके। यहां यह बात विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट का 28 घंटे का आदेश नही होता और यदि येदियुरप्पा सरकार को 15 दिनों का ही समय मिला होता तो शायद उनकी की कुर्सी बचने की संभावनाएं बढ़ सकती थी ,परंतु न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। भाजपा मायूस हो गई और कांग्रेस की बाहें खिल गई। इसे लोकतंत्र की जीत कहा जाए या राजनीतिक विडंबना कि 104 सीटें जीतकर बहुमत से मात्र आठ स्थान दूर बैठी भाजपा को मनमसोसकर विपक्ष में बैठना होगा,वही मात्र 38 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रहने वाली जेडीएस के हाथों में गठबंधन के कारण मुख्यमंत्री पद की बागडौर आ गई। 78 सीटें जीत कर दूसरे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस की कृपा से जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य तो मिल गया है, किन्तु यह 1996 की तरह दोहराया नही जाएगा यह कहना मुश्किल है। गौरतलब है कि 1996 में अटलजी जी सरकार गिरने के बाद जेडीएस नेता एक डी देवेगौड़ा कम सीटें होने के बाद भी कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए थे ,लेकिन उन्हें जल्द ही कांग्रेस के कोप का भागी बन कुर्सी छोड़ना पड़ा था। भाजपा तो यह मान चुकी है कि इस स्थिति को आने में ज्यादा समय नही लगेगा।

कांग्रेस एवं जेडीएस इस हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ है कि अगले लोकसभा चुनाव तक गठबंधन बनाए रखने में उनका ही फायदा है।

सत्ता में रहते हुए यदि वे संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे तो राज्य में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में होंगे। बिहार में कुछ इस तरह का प्रयोग राजद एवं जेडीयू मिलकर कर चुके है, और उसमें वह सफल भी हुए थे।

मन की दौलत

एक महर्षि थे। उनका नाम था कणाद। किसान जब अपना खेत काट लेते थे तो उसके बाद जो अन्न-कण पड़े रह जाते थे, उन्हें उठाकर वे अपना जीवन चलाते थे। इसी से उनका यह नाम पड़ गया। जब राजा को पता चला तो उसने बहुत-सा पैसा देकर अपने मंत्री को उनके पास भेजा। मंत्री पहुंचा तो महर्षि ने कहा–मैं ठीक

हूं। इस धन-दौलत को तुम उन लोगों में बांट दो, जिन्हें इसकी जरूरत है। राजा खुद उनके पास बहुत-सा पैसा ले गया। महर्षि बोले-यह उन्हें दे दो, जिनके पास कुछ नहीं है। उसने लौटकर पूरी कहानी अपनी रानी से कही। वह बोली-ऐसे साधु के पास कुछ देने के लिए नहीं, लेने के लिए जाना चाहिए। राजा महर्षि के पास गए और माफी मांगी। कणाद ने कहा-गरीब कौन है? मुझे देखो और अपने को देखो। बाहर नहीं, भीतर। मैं कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए अचानक ही सम्राट हो गया हूं। एक धन-दौलत बाहर है और एक भीतर है। जो बाहर है, वह आज या कल छिन ही जाती है। इसलिए जो जानते हैं, वो उसे सम्पदा नहीं, विपदा मानते हैं। जो भीतर है, वह मिलती है तो खोती नहीं। उसे पाने पर फिर कुछ भी पाने को नहीं रह जाता।

ट्रम्प के बरक्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सोमवार को हुई मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा अहमियत इसे हाल की कुछ घटनाओं ने दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपतिडॉनल्ड ट्रम्प ने अपनी 'अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी' के तहत जो आक्रामक तेवर दिखाए हैं, उसका प्रभाव किसी एक देश या खास समझौते तक सीमित नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पिछले साल पारित सीएएटीएस (काउंटरिंग अमेरिकाज ऐडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस) एक्ट की जद में केवल रूसी कंपनियां नहीं बल्कि उनसे कारोबार करने वाली अन्य देशों की कंपनियां भी आती हैं। इसी आधार पर अमेरिका ने हाल में भारत को भी आगाह किया कि वह रूस के साथ कोई बड़ा रक्षा सौदा करने की न सोचे। ध्यान रहे, भारत किसी भी अन्य देश के मुकाबले रूस से ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदता है। रूस भारत का एक विश्वस्त मित्र और सहयोगी देश रहा है। स्वाभाविक ही भारत ने अमेरिका से दो टूक कह दिया कि वह अपनी रक्षा जरूरतों को किसी और देश के आग्रहों से प्रभावित नहीं होने देगा। ऐसे में मोदी और पुतिन की इस मुलाकात को अमेरिका के बरक्स दोनों देशों की बढ़ती करीबी के एक मजबूत

संकेत के रूप में लिया जाना स्वाभाविक है। इसी संदर्भ में एक अन्य बड़े देश चीन का यह कहना काफी मायने रखता है कि वह व्यापार घाटा कम करने के अमेरिकी आग्रहों के मद्देनजर अपना निर्यात घटाने और आयात बढ़ाने के सुझाव पर विचार करने को तैयार है। हालांकि यह तय करना फिलहाल मुश्किल है कि चीनी निर्यात कम होने से अमेरिकी जनता और इंडस्ट्री के किस हिस्से को अंततः कितना नफा या नुकसान होगा, पर इस बात की पूरी संभावना है कि चीन की यह घोषणा ट्रम्प को अपना रवैया जारी रखने के लिए प्रेरित करे।

इसी बिंदु पर यह भी देखा जा सकता है कि ईरानी परमाणु समझौते से बाहर आने का फैसला पहली नजर में भले ट्रम्प की छवि बेहतर बनाता लगे, पर मौजूदा हालात में ईरान पर पाबंदियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमत बढ़ाएंगी, जिससे भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था मुश्किल में पड़ सकती है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट का मामला भी अटक सकता है, जो सिर्फ भारत और ईरान तक सीमित एक आर्थिक प्रॉजेक्ट नहीं है। यह अफगानिस्तान पहुंचने की वह अकेली कारगर राह है जो पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती।

आतंकवाद पर काबू पाने के लिहाज से भी इसका एक वैश्विक महत्व है। कुल मिलाकर ये जटिलताएं बताती हैं कि आज की हमारी दुनिया आपस में इस कदर घुली-मिली है कि कोई भी एक देश अपने हितों को बाकी सबसे अलग मानकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि आज के दौर के शीर्ष नेता नारेबाजी में न उलझें और संवेदनशील मसलों पर अधिक गंभीरता व उदारता का परिचय दें।

नक्सली नासूर

एक बार फिर माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में नक्सलवादियों द्वारा किये गये भीषण विस्फोट में सुरक्षा बलों के सात जवान मारे गये। यह घटना तब हुई जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इलाके का दौरा करना था। मुख्यमंत्री रमन सिंह विकास यात्रा निकालने जा रहे थे। सुरक्षा बलों के जवान एक निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा चौकसी में?थे। पिछले कुछ महीनों में पुलिस माओवादियों पर भारी पड़ती नजर आ? रही थी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम द्वारा मार्च के पहले हफ्ते में दस नक्सलियों को मारने का दावा किया गया था, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे। दो माह पहले भी माओवादियों ने सुकमा में सुरक्षा बल के 9 जवानों की हत्या कर दी थी। यह सिलसिला सालों से जारी है मगर समस्या का कोई कारगर समाधान नहीं दिखता। नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यह नक्सलियों के खिलाफ चलायी जा रही मुहिम की सफलता से उपजी बौखलाहट है। इससे पहले नोटबंदी के दौरान भी दावा किया गया था कि इस मुहिम से नक्सलवादियों की कमर टूट गई है। मगर नक्सलवादी फिर उसी ताकत से हमले कर रहे हैं, आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं

और सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या कर हथियार लूट रहे हैं।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नक्सल विरोधी मुहिम सिरे क्यों नहीं चढ़ रही है? कब तक जवानों का रक्त यूं ही बहता रहेगा? क्यों उन्हें बारूदी सुरंग खोजने की आधुनिक तकनीक व सुरक्षा के संसाधन ?उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं? क्या इस समस्या के राजनीतिक समाधान की गंभीर कोशिश नहीं की जानी चाहिए? क्यों स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों की खुफिया एजेंसियां ऐसे हमलों को रोक पाने में विफल रहती हैं? क्यों स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल नहीं हो पा रहा है कि नक्सलियों की गतिविधियों की पुख्ता जानकारी मिल पाए। दरअसल, नक्सलवादियों की लड़ाई परंपरागत जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर हक की रही है। औद्योगिक घरानों ने जिस निर्ममता से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, उससे भी क्षेत्र में आक्रोश पनपा। हमें विकास की विसंगतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। शासकीय व प्रशासनिक संवेदनहीनता से इतर आदिवासियों की वाजिब मांगों को सुना जाना चाहिए। यूं ही कोई मरने-मारने पर ?उतारू नहीं होता। नक्सलवादियों को भी समझाया जाना चाहिए कि विकास के जरिये ही वे देश की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। उन्हें संविधान व कानून के दायरे में बातचीत के लिये आगे आना चाहिए। गुरिल्ला युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इस खूनी संघर्ष की कीमत बेकसूर लोगों को चुकानी पड़ रही है।

खाना-खजाना

फ्राइड राइस समोसा

कितने लोगों के लिए : 2

सामग्री :

2 कप मैदा, मोयन के लिए तेल, नमक और तलने के लिए तेल

फिलिंग के लिए : 1 कप उबले हुए चावल, 1 कप बारीक कटी सब्ज़ियां, 1 टेबलस्पून टमैटो सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, नमक, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, रिफाइंड ऑयल

विधि :

पैन में तेल गर्म करें। इसमें सभी सब्ज़ियां डालकर हलका गलने तक पकाएं। फिर उसमें चावल और सभी तरह की सॉस डालें। तेज़ आंच पर सॉते करें। नमक मिलाकर चावल को 2 मिनट तक भूनें। आंच से उतार कर ठंडा करें और हरा धनिया मिलाएं।

मैदे में मोयन और नमक डालकर गूंथें। इससे तैयार लोइयों को बेल कर बीच में से काट लें। हर भाग में तैयार फ्राइड राइस की फिलिंग भरें और तिकोना मोड़कर पानी लगाकर बंद कर दें।

गर्म तेल में समोसों को तल लें। हरी चटनी के साथ सर्व करें।